गरवी गुजरात

TITLE CODE:- UPHIN51504

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 211
दि. 02.12.2025,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में 60वें डीजीपी-आईजीपी सम्मेलन की अध्यक्षता की

(जीएनएस)।

छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत के उच्चतम पुलिस नेतृत्व ने एक ही मंच पर उपस्थिति दर्ज की, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 नवंबर 2025 को 60वें अखिल भारतीय डीजीपी-आईजीपी सम्मेलन का उद्घाटन किया और उसका नेतृत्व किया। नया रायपुर स्थित आईआईएम परिसर में आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत की आंतरिक सुरक्षा प्रणाली को 'विकसित भारत, सुरक्षित भारत' की व्यापक दृष्टि के अनुरूप नए सिरे से तैयार करना था — अर्थात विकास को आधार बनाकर एक सुरक्षित और सशक्त भारत का निर्माण।

डीजीपी-आईजीपी सम्मेलन एक वार्षिक राष्ट्रीय-स्तरीय आंतरिक सुरक्षा बैठक है, जिसका आयोजन इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) द्वारा किया जाता है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के अधीन कार्य करता है।

यह सम्मेलन भारत में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विचार-विमर्श के लिए सर्वोच्च मंच के रूप में कार्य करता है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक (DGs) और पुलिस महानिरीक्षक (IGs) शामिल होते हैं।

इस सम्मेलन में प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों — जैसे रॉ (RAW), राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA), एनटीआरओ (ठळफ्ड), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (ठउइ), तथा विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) — की भी भागीदारी होती है। ये सभी मिलकर नीतिगत निर्माण, उभरते सुरक्षा खतरों, और अंतर-एजेंसी समन्वय पर महत्वपूर्ण चर्चाएँ करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए इसे ऐसा महत्वपूर्ण मंच बताया, जहाँ विभिन्न राज्यों की पुलिस सर्वश्रेष्ठ प्रथाएँ साझा करती हैं, सुरक्षा नवाचारों पर चर्चा करती हैं और कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के बीच राष्ट्रीय एकजुटता को मजबूत करती हैं।

उन्होंने आंतरिक सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया और राज्य व केंद्र की पुलिस बलों से नवाचारी पुलिसिंग तरीकों, बेहतर समन्वय, तथा नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने का आ'ान किया।

सम्मेलन के प्रमुख विषय

1. आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था

विभिन्न राज्यों के पुलिस प्रमुखों ने कानून-व्यवस्था, पूर्व सिफारिशों के क्रियान्वयन, तथा संगठित अपराध,

आतंकवाद और उग्रवाद से उत्पन्न खतरों पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दीं। सम्मेलन में अपराध जाँच क्षमता सुधारने, बेहतर डेटा-विश्लेषण अपनाने और एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।

2. फॉरेंसिक और तकनीक-आधारित पुलिसिंग पर फोकस

सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा फॉरेंसिक तकनीक और अपराध जाँच में उसकी बढ़ती भूमिका पर केंद्रित रहा। इस दौरान निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई —

फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं और विशेषज्ञ कर्मियों का विस्तार

डिजिटल सबूत तथा एआई टूल्स का उपयोग कर अपराध समाधान

राज्यों के बीच निर्बाध डेटा-शेयरिंग तंत्र विकसित करना

3. महिलाओं की सुरक्षा

महिला सुरक्षा को पारंपरिक और तकनीक-आधारित दोनों तरीकों से मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई। प्रस्तावित प्रमुख कदम —

सीसीटीवी निगरानी में वृद्धि

पैनिक अलर्ट ऐप्स और 247 आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियाँ

स्मार्ट मॉनिटरिंग के माध्यम से सुरक्षित शहरी स्थानों का विकास

बस्तर 2.0: छत्तीसगढ़ में पोस्ट-नक्सल रणनीति

छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम ने 'बस्तर 2.0' नामक प्रस्तुति दी — जो मार्च 2026 तक नक्सलवाद की समाप्ति के लक्ष्य के बाद बस्तर क्षेत्र के विकास का रोडमैप है।

'बस्तर 2.0' के मुख्य बिंदु —

उग्रवाद-मुक्ति के बाद सुरक्षा उपलब्धियों को स्थिर रखना

आदिवासी क्षेत्रों में सड़क तथा बुनियादी ढाँचे का विस्तार

स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी सरकारी सेवाएँ पहुँचाना

स्थानीय शासन व जनभागीदारी को प्रोत्साहन

यह योजना संघर्ष-नियंत्रण से विकास-केंद्रित बस्तर की ओर ऐतिहासिक परिवर्तन का संकेत है।

विजन 2047: भविष्य की पुलिसिंग का रोडमैप

सम्मेलन में वर्ष 2047 तक की दीर्घकालिक पुलिसिंग दृष्टि भी प्रस्तुत की गई, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा। प्रमुख लक्ष्य —

आधुनिक, डिजिटाइज्ड और सेवा-उन्मुख पुलिस बल

प्रशिक्षण, जनविश्वास और जवाबदेही पर अधिक ध्यान

फॉरेंसिक, साइबर और एआई-सक्षम जाँच क्षमताओं का विस्तार

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में नागरिक-अनुकूल पुलिसिंग सिस्टम का निर्माण

यह दूरदर्शी योजना भारत को भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करने पर केंद्रित है।

मुख्य तथ्य

सम्मेलन का नाम: 60वाँ अखिल भारतीय डीजीपी-आईजीपी सम्मेलन

तारीख: 29 नवंबर 2025

स्थान: आईआईएम परिसर, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

थीम: विकसित भारत, सुरक्षित भारत

'प्रधानमंत्री सबसे बड़े ड्रामेबाज', पीएम के बयान पर कांग्रेस का पलटवार- असल मुद्दों पर चर्चा करें

नई दिल्ली (जीएनएस)।

संसद सत्र की शुरूआत में मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 'मेरा आग्रह रहेगा कि संसद में चर्चा को गंभीरता से लें, ड्रामा करने के लिए बहुत जगह होती है, जिसे करना है करता रहे, यहां ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए।'

कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए उन निशाना साधा है और प्रधानमंत्री को सबसे बड़े ड्रामेबाज तक कह दिया। कांग्रेस का यह बयान तब आया है, जब संसद के शीतकालीन सत्र की शुरूआत से पहले मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष संसद में ड्रामा कर रहा है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष से पराजय की बौखलाहट को भुलाकर संसद में सार्थक चर्चा करने की अपील की।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा एक पोस्ट में आरोप लगाया कि लोगों के असल मुद्दों को सुलझाने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर ड्रामेबाजी की है। खरगे ने कहा कि 'सरकार बीते 11 वर्षों से लगातार संसदीय मयार्दा और व्यवस्था को रौंद रही है और ऐसी घटनाओं की लंबी फेहरिस्त मौजूद है।' खरगे ने लिखा, 'भाजपा को अब लोगों का ध्यान भटकाने वाले इस ड्रामे को खत्म करके संसद में असल मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए और लोगों का सामना करना चाहिए।'

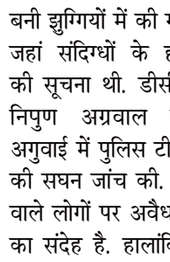

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'आम आदमी बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता और देश के संसाधनों की लूट से जूझ रहा है। जो लोग सत्ता में हैं, वे ड्रामेबाजी का खेल खेल रहे हैं और सत्ता के अहंकार से भरे हैं।' खरगे ने कहा, 'एसआईआर प्रक्रिया में काम के बोझ के कारण बीएलओ लगातार जान दे रहे हैं। विपक्ष, वोट चोरी सहित अन्य मुद्दों को प्राथमिकता देना चाहता है और संसद में हम इसे लगातार उठाएंगे।'

संसद सत्र की शुरूआत में मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 'मेरा आग्रह रहेगा कि संसद में चर्चा को गंभीरता से लें।

लोकसभा में हंगामे के बीच पीएम मोदी के चेंबर में अहम बैठक, अभिनेता धमेंद्र को दी गई श्रद्धांजली

संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही सियासी तापमान बढ़ गया है. रक्फ को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस देखने को मिली,

जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. इस सत्र में सरकार का फोकस 14 अहम विधेयकों को पास कराने पर है, जिनमें दिवाला कानून, बीमा कानून, सिक्योरिटीज मार्केट, कॉपोरेट कानून, राष्ट्रीय राजमार्ग, उच्च शिक्षा आयोग, एटॉमिक एनर्जी, जीएसटी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बिल शामिल हैं.

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में अहमदाबाद में राष्ट्र निर्माण में पारसियों द्वारा महामूल्यवान योगदान देने वाले पारसी धर्मगुरुओं का किया गया सम्मान

- राष्ट्र निर्माण में पारसियों का महामूल्यवान योगदान रहा है
- मैडम भीकाजी कामा, होमी भाभा, टाटा, वाडिया, गोदरेज परिवारों, फील्ड मार्शल माणेक शॉ आदि पारसियों का बड़ा योगदान रहा है
- दानवीरता का दूसरा नाम पारसी हैं, पारसियों ने भगवद् गीता का 'स्वधर्म' का संदेश आत्मसात किया है

गांधीनगर,01 दिसंबर :मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में सोमवार को अहमदाबाद में पारसी धर्मगुरुओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के करकमलों से पारसी धर्मगुरुओं को सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सभी को गीता जयंती की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपने धर्म में निष्ठापूर्वक जीना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। पारसी समाज के पूर्वजों ने भारत में आकर गीता के 'स्वधर्म' के संदेश को जिया और कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ा है। पारसियों ने भगवद् गीता का स्वधर्म का संदेश आत्मसात किया है। अपने धर्म की रक्षा के लिए 1300 वर्ष पहले वे ईरान से स्थानांतरण कर गुजरात आए और दूध मे चीनी की तरह घुल गए। राष्ट्र निर्माण में पारसियों का महामूल्यवान योगदान रहा है। श्री पटेल ने कहा कि जिस

तरह भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के ज्ञान को सदियों से जतन करके रखा गया है, उसी तरह पवित्र आतश की रक्षा से धर्म का अस्तित्व बनाए रखने की गाथा का युगों तक जतन करने के लिए नवसारी में टाइम कैप्सूल रखकर इतिहास को अमर रखने का कार्य पारसी समुदाय द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को यह टाइम कैप्सूल चरितार्थ करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की जो विभावना दी है, उसे पारसी समुदाय ने साकार किया है। साथ ही; उन्होंने पारसी समाज के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में शुरू की गई पीएम जियो पारसी योजना का भी उल्लेख किया। पारसी समाज गुजरात के सामाजिक जीवन में समरसता से घुल गया होने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जहाँ-जहाँ यह समुदाय बसा, वहाँ दानवीरता-परोपकारिता का बीजारोपण हुआ है।

उनके पूर्वजों ने हमेशा समाज को कुछ न कुछ दिया है। इसीलिए कहा जाता है कि दानवीरता-परोपकारिता का दूसरा नाम पारसी हैं। अरीज खंभाता बेनेवोलेंट ट्रस्ट (एकेबेटी) पारसी समाज की दानवीरता की उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री ने जोड़ा कि यह ट्रस्ट हेल्थकेयर, एजुकेशन तथा समाज कल्याण सहित विभिन्न क्षेत्रों में वंचित समुदाय के उत्थान के लिए समर्पित रहा है। एचआईवी पीड़ित लोगों के लिए भी यह ट्रस्ट कल्याण के अनेक कार्य करता है। ट्रस्ट के माध्यम से हर वर्ष हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है।

श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर कहा कि अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी पारसी समुदाय ने अपने संस्कारों, मूल्यों तथा सूझ-बूझ को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम काल से लेकर आज तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपना देने वाले मैडम भीकाजी कामा, होमी भाभा, टाटा, वाडिया, गोदरेज परिवारों, फील्ड मार्शल सैम माणेक शॉ, फरदुनजी मर्जबान, नानी पालखीवाला, सोली सोराबजी, फली नरीमान सहित पारसी अग्रणियों को इस अवसर पर याद किया।

पारसी समुदाय के प्रमुख धार्मिक अग्रणी दस्तूरजी श्री खुर्शीद दस्तूर ने अरीज खंभाता बेनेवोलेंट ट्रस्ट के कामकाज की प्रसंसा करते हुए शुभकामनाएँ दीं।

अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए - दुनिया भर में लोकतंत्र का समर्थन करते हुए 30 वर्ष

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और देश के सभी चुनाव कर्मियों द्वारा कराए गए स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को दुनिया भर में

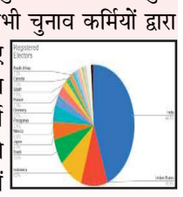

पहचान मिलने के बाद, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार तीन दिसंबर 2026 को स्वीडन के स्टॉकहोम में भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान (अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए) के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने वाले हैं।

अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए 1995 में स्थापित हुआ, यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसके वर्तमान में 35 सदस्य देश हैं तथा अमेरिका और जापान पर्यवेक्षक (ऑब्जर्वर) के रूप में शामिल हैं।

अवैध बांग्लादेशियों पर योगी सरकार का कड़ा एक्शन

लखनऊ (यूपी): (जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में रह रहे बांग्लादेशियों को तलाश कर डिटेंशन सेंटर में भेजने के सख्त निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है. इसी क्रम में आज लखनऊ पुलिस ने राजधानी में एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया. यह कार्रवाई मुख्य रूप से लखनऊ एयरपोर्ट के आसपास बनी झुग्गियों में की गई, जहां संदिग्धों के होने की सूचना थी. डीसीपी निपुण अग्रवाल की अगुवाई में पुलिस टीम ने इन इलाकों की सघन जांच की. झुग्गियों में रहने वाले लोगों पर अवैध बांग्लादेशी होने का संदेह है. हालांकि, ये लोग खुद को असम का मूल निवासी बताते हैं.

कूड़ा बीनने का काम और दस्तावेजों का दावा

निवासियों का दावा है कि वे लगभग 13 साल पहले रोजी-रोटी की तलाश में लखनऊ आए थे और अब

यहीं कूड़ा बीनने का काम करते हैं. पुलिस की जांच के दौरान इन संदिग्धों ने अपने पास आधार कार्ड, एनआरसी (NRC) और अन्य संबंधित दस्तावेज होने का दावा किया. उन्होंने कहा कि जब उनके पास वैध दस्तावेज हैं, तो उन्हें पुलिस की जांच से डरने की कोई बात नहीं है.

डिटेंशन सेंटर भेजने की तैयारी

फिलहाल, केवल लखनऊ ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में संदिग्ध विदेशी नागरिकों की तलाश का अभियान जोर-शोर से चलाया जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि जितने भी अवैध बांग्लादेशी मिलेंगे, उन्हें पकड़कर डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा. इसके बाद, कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें वापस उनके देश भेजने की कार्रवाई की जाएगी.

धार के धामनोद में किसानों का शांतिपूर्ण आंदोलन, 5,000 किसान हाईवे पर डटे

(जीएनएस)।

मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले शुरू हुआ किसान महाकुंभ सोमवार को चरम पर पहुंच गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी, कर्जमाफी, बिजली दरों में कटौती, फसल बीमा की पारदर्शिता और पुराने वादों पर अमल जैसी मांगों को लेकर धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और अलीराजपुर जिले के करीब 5,000 किसान नेशनल हाईवे-52 (मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग) के खलघाट टोल प्लाजा पर डटे हुए हैं।

जिला प्रशासन ने आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए संपूर्ण धार जिले में धारा 144 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163) लागू कर दी है, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया कि उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। वे रात हाईवे पर ही गुजारेंगे और मंगलवार सुबह नई रूपरेखा तैयार करेंगे।

सोमवार शाम तक आंदोलन का दायरा बढ़ता गया। किसानों ने हाईवे के बीचोंबीच पेड़ और लकड़ियां रखकर चक्का जाम किया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया। पुलिस ने फोरलेन की एक लेन पर ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश की, तो किसानों ने वाहन रुकवाकर विरोध जताया। प्रशासन ने 400 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया है, और ड्रोन से निगरानी तेज कर दी गई है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा, "किसान अपनी मांगें शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन के माध्यम से रख सकते हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 जरूरी थी।" लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि पिछले 5 महीनों में कई आवेदन दिए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई।

आंदोलन का बैकग्राउंड: 5 जिलों

36 साल बाद रुबैया सईद किडनैपिंग केस में CBI ने 1 आरोपी को किया अरेस्ट, पूर्व गृह मंत्री की बेटी से जुड़ा केस

केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के 1989 के अपहरण मामले में सीबीआई को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 35 साल से फरार

चल रहे शफात अहमद शांगलू को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर के इश्बर निशात क्वार्टर का शफात अहमद शांगलू अपहरण में शामिल होने का आरोपी है। 36 साल पुराने इस संवेदनशील मामले में इस गिरफ्तारी ने नई जान फूंक दी है।

बता दें रुबैया सईद को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के आतंकवादियों ने अगवा किया था।

सम्पादकीय

प्रशासनिक प्रक्रिया के उलझाव में अटकी ध्वस्तीकरण कार्यवाई

जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रादेश होने के कारण सत्ता राज्य और केंद्र दोनों में विभाजित है, यही कारण है कि जब भी कोई फैसला उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यालय से आता है तो राज्य सरकार पल्ला झाड़ लेती है और यदि कोई आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय से आता है तो उपराज्यपाल कार्यालय चुप्पी साध लेता है। इसका परिणाम यह होता है कि राज्य के प्रशासनिक अधिकारी अपने मनमर्जी से फैसले भी ले रहे हैं और उसे लागू करके लोगों को चौंका रहे हैं। अभी बृहस्पतिवार को जम्मू के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक पत्रकार का घर जम्मू-विकास प्राधिकरण यानि जेडीए ने ध्वस्त कर दिया। राज्य सरकार का कोई बड़ा-छोटा मंत्री या मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोला। किन्तु जब शुक्रवार और शनिवार को हंगामा बढ़ गया तो भाजपा के नेता रविन्दर रैना ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की, पता चला कि वहां से ध्वस्तीकरण का कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ था। अब भाजपा के लोगों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि जेडीए की कार्रवाई हो रही है और प्रातिदिन अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान ध्वस्तीकरण हो रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री गहरी निन्द्रा में होने के कारण किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस आलोचना के बाद राज्य सरकार के उपमुख्यमंत्री सुरिन्दर चौधरी सामने आए और उन्होंने राज्य सरकार की तरफ से सफाई दी कि पत्रकार का घर गिराने का आदेश मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। दरअसल राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। यदि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जम्मू में तेजी से चल रही है तो किसी का भी घर कार्रवाई के दायरे में आ सकता है। जब भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्राधिकरण के लोग लेते हैं तो इसकी जानकारी केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल के सचिव, मुख्यमंत्री के प्राधान सचिव, राज्य के मुख्य सचिव एवं राज्य के पुलिस प्राुख को अवश्य होती है क्योंकि प्राधिकरण के आयुक्त कार्रवाई के पहले उक्त अधिकारियों को सूचित करने के लिए प्रशासनिक प्राक्रिया के तहत बाध्य हैं। ऐसे में उपरोक्त कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस बात से इंकार कर ही नहीं सकता कि पत्रकार डैंग के घर के ध्वस्तीकरण की पूर्व सूचना उसे नहीं थी। उपमुख्यमंत्री सुरिन्दर चौधरी ने जिस तरह दावा किया कि मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश ही नहीं था फिर पत्रकार का घर कैसे ध्वस्त हुआ? चौधरी ने यह भी कहा कि ध्वस्तीकरण में सहयोग पुलिस ने दिया और पुलिस उपराज्यपाल के तहत है, इसलिए उपराज्यपाल को जांच करानी चाहिए कि ध्वस्तीकरण का यह आदेश किसने दिया? सच तो यह है कि डैंग के घर गिरने के बाद अब राज्य सरकार यह साबित करना चाहती है कि उसने इस संदर्भ में कोई निर्देश नहीं दिया। बिल्वुल सही न तो मुख्यमंत्री इस तरह का निर्देश देते और न ही उपराज्यपाल। निर्देश तो तीसरे सबसे बड़े अधिकारी राज्य के मुख्य सचिव भी नहीं देते। निर्देश तो जारी होता है विकास प्राधिकरण के कार्यालय से और तत्संबंधी सूचनाएं ही भेजी जाती हैं। उपमुख्यमंत्री के दावे मात्र नेताजी की राजनीतिक अभिनय है। पहले तो एक सामान्य पत्रकार की चिन्ता नहीं की गईं और अब अपने बचाव में भ्रामक बयान दिए जा रहे हैं। हैरानी की बात है कि यदि पत्रकार डैंग का घर अवैध रूप से अतिक्रमण करके बनाया गया था तो जम्मू की स्थानीय निकाय के अधिकारी और कर्मचारी क्या कर रहे थे! बहरहाल यह घटना सरकार के लिए बहुत छोटी है किन्तु एक पत्रकार जो समाज का सामान्य प्राणी है, उसके लिए तो बहुत बड़ी विपत्ति की स्थिति है। कुछ राज्यों को छोड़कर पत्रकार सरकार की नजरों में इसी तरह उपेक्षा के शिकार हैं। जब तक सरकारें पत्रकारों के पाति संवेदनशील नहीं होंगी, पत्रकारों के प्राति इसी तरह अधिकारी अनियंत्रित होकर कार्रवाई करते रहेंगे। यदि अधिकारी यह समझ पाएं कि पत्रकार का घर ध्वस्त करने पर उसी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी तो अधिकारी भी पत्रकारों के प्राति संवेदनशील हो जाएंगे। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो पत्रकार लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कराने के माध्यम माने जाते हैं, उन्हें भी शासकीय तंत्र के संवेदनहीनता का शिकार होना पड़ता है।

राज्यसभा के सभापति श्री सी.पी. राधाकृष्णन के अभिनंदन के दौरान पीएम मोदी का वक्तव्य

श्री सी.पी. राधाकृष्णन जी एक साधारण कृषक पृष्ठभूमि से आते हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन जन सेवा के लिए समर्पित किया है: प्रधानमंत्री

सेवा, समर्पण और संयम श्री सी.पी. राधाकृष्णन जी के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग रहे हैं: प्रधानमंत्री

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज पहली बार राज्यसभा की अध्यक्षता करने पर उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने इस दिन को राज्यसभा के सभी माननीय सदस्यों के लिए गौरव का क्षण बताया। सभापति का हार्दिक स्वागत करते हुए, श्री मोदी ने कहा, "इस सदन की ओर से और अपनी ओर से, मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि इस उच्च सदन के सभी माननीय सदस्य इस प्रतिष्ठित संस्था की गरिमा को सदैव बनाए रखेंगे और अपनी गरिमा बनाए रखने के प्रति भी सदैव सजग रहेंगे। यह मेरा आपको दृढ़ आश्वासन है।"

श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि चूंकि शीतकालीन सत्र में प्रमुख राष्ट्रीय मामलों पर विचार-विमर्श किया जाएगा, इसलिए सभापति का नेतृत्व राज्यसभा के कामकाज को और समृद्ध बनाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान परिवार से आने वाले चेयरमैन श्री राधाकृष्णन ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया। श्री मोदी ने कहा, "समाज सेवा उनकी निरंतर पहचान रही है। राजनीति तो बस एक पहलू थी, सेवा भावना उनके जीवन के मूल में रही।" प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जन कल्याण के प्रति उनकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो समाज सेवा को महत्व देते हैं।

अध्यक्ष के व्यापक सार्वजनिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने कॉयर बोर्ड को एक ऐतिहासिक रूप से अत्यधिक कार्यनिष्पादन करने वाली संस्था में बदलने में उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पुडुचेरी में राज्यपाल और उपराज्यपाल के रूप में

उनकी समर्पित सेवा की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने झारखंड के आदिवासी समुदायों के साथ उनके गहन जुड़ाव की विशेष रूप से प्रशंसा की, जहां वे अक्सर दूर-दराज के गांवों की यात्रा करते थे और लोगों की जरूरतों को समझने के लिए छोटी-छोटी बस्तियों में रात बिताते थे। उन्होंने कहा, "राज्यपाल के पद पर रहते हुए भी आपकी सेवा भावना और भी निखरती गई।"

वर्षों के जुड़ाव के अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री राधाकृष्णन प्रोटोकॉल की सीमाओं से ऊपर उठकर खुद को अलग पहचान देते हैं। श्री मोदी ने जोर देकर कहा, "सार्वजनिक जीवन में, प्रोटोकॉल से परे जीने की एक विशेष शक्ति होती है और हमने हमेशा आपमें वह शक्ति देखी है।" प्रधानमंत्री ने कहा कि हालांकि सभापति श्री राधाकृष्णन का जन्म "डॉलर सिटी" में हुआ था, जो अपनी एक मजबूत पहचान वाला स्थान है, फिर भी उन्होंने डॉलर सिटी के उन लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना चुना जो उत्पीड़ित, हाशिए पर पड़े या वंचित समुदायों से थे।

प्रधानमंत्री ने बताया कि बचपन में श्री सी.पी. राधाकृष्णन को एक बार मृत्यु का अनुभव हुआ था जब वे अविनाशी मंदिर के तालाब में डूबते-डूबते बचे थे। उन्होंने बताया कि सभापति और उनका परिवार अक्सर उनके बच जाने को ईश्वरीय कृपा बताते हैं। एक और जानलेवा घटना का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने कोयंबटूर में हुए विनाशकारी बम विस्फोट का जिक्र किया जो श्री लाल कृष्ण आडवाणी की निर्धारित यात्रा से कुछ समय पहले हुआ था। इस विस्फोट में लगभग 60 से 70 लोगों की जान चली गई थी और सभापति बाल-बाल बच गए थे।

श्री मोदी ने कहा, "इन घटनाओं ने, जिन्हें वे ईश्वरीय हस्तक्षेप के संकेत मानते हैं, समाज की सेवा में स्वयं को और अधिक समर्पित करने के उनके संकल्प को और भी अधिक मजबूत किया।" उन्होंने कहा कि ऐसे जीवन के अनुभवों को और अधिक सकारात्मकता और प्रतिबद्धता में बदलना सभापति के उल्लेखनीय व्यक्तित्व को दशार्ता है।

प्रधानमंत्री ने बताया कि सभापति श्री राधाकृष्णन अपनी पहली काशी यात्रा के दौरान मां गंगा के आशीर्वाद से अत्यंत प्रेरित हुए और उन्होंने मांसाहार त्यागने का व्यक्तिगत संकल्प लिया। यह निर्णय आहार संबंधी किसी भी निर्णय के बजाय उनकी आध्यात्मिक संवेदनशीलता और आंतरिक प्रेरणा को दशार्ता है। श्री मोदी ने कहा, "आपके नेतृत्व के गुण आपके छात्र जीवन से ही स्पष्ट हैं। आज, आप राष्ट्रीय नेतृत्व की दिशा में हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए यहां उपस्थित हैं। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है।"

पारंपरिक कलाकारों को वित्तीय सहायता

(जीएनएस)।

संस्कृति मंत्रालय द्वारा कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) नामक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम संचालित की जाती है, जिसमें शामिल विभिन्न स्कीम घटकों के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य सहित देश की पारंपरिक कलाओं और विभिन्न प्रकार की मंच कलाओं में अभ्यासरत संगठनों/कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों का संक्षिप्त ब्यौरा अनुलग्नक-क पर दिया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत देश भर में राज्य-वार प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि और सहायता प्राप्त सांस्कृतिक संगठनों/व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक-कक पर दिया गया है।

संस्कृति मंत्रालय द्वारा कला एवं संस्कृति से संबंधित स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कोई वित्तीय योजना संचालित नहीं की जाती है।

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने और वैश्विक क्षेत्र में भारत की छवि को अनुकूल रूप से संवर्धित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा "वैश्विक भागीदारी स्कीम" नामक योजना कार्यान्वित की जाती है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कला एवं संस्कृति सहित भारतीय कला रूपों में अभ्यासरत कलाकारों को 'भारत महोत्सव' बैनर के तहत विदेशों में प्रस्तुति देने का अवसर प्रदान करना है।

सरकार पारंपरिक कला रूपों सहित कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों को परिरक्षित, संवर्धित और प्रोत्साहित करने में निरंतर प्रयासरत रही है। भारत सरकार ने सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जेडसीसी) स्थापित किए हैं जिनके मुख्यालय पटियाला (पंजाब), नागपुर (महाराष्ट्र), उदयपुर (राजस्थान), प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), दीमापुर (नागालैंड) और तंजावुर (तमिलनाडु) में स्थित हैं। ये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र देश भर में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों और कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन करते हैं। इसके लिए वे पूरे भारत से लोक/जनजातीय कलाकारों को शामिल करते हैं जो इन कार्यक्रमों

के दौरान अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं।

यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

अनुलग्नक-क

गुरु-शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)

इस योजना का उद्देश्य नाट्य समूहों, रंगमंच समूहों, संगीत मंडलियों, बाल रंगमंच आदि जैसे मंचकला कार्यकलापों की सभी शैलियों तथा गुरु-शिष्य परंपरा के अनुरूप नियमित आधार पर कलाकारों को उनके संबंधित गुरु द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अनुसार, रंगमंच, संगीत और नृत्य के क्षेत्र में 1 गुरु और अधिकतम 18 शिष्यों को सहायता प्रदान की जाती है। गुरु के लिए 15000/- रु. प्रतिमाह, कलाकारों की आयु के अनुरूप शिष्य के लिए 2000-10000/- रुपए प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान की जाती है।

2. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता: इस स्कीम में निनलिखित घटक शामिल हैं :

. राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य पूरे देश में कला और संस्कृति के संवर्धन में शामिल राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों का संवर्धन और उन्हें सहायता प्रदान करना है। यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत 5 वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के तहत सहायता की राशि 1.00 करोड़ रुपये तक है जिसे विशेष मामलों में 5.00 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

. सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/ सोसाइटियों/ न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपए का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष परिस्थितियों में 20.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

. हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

कोयला मंत्रालय ने कुशल और टिकाऊ कोयला अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए 'अन्वेषण कार्यक्रमों और भूवैज्ञानिक रिपोर्टों' के लिए सरल अनुमोदन कार्यप्रणाली की शुरूआत की

(जीएनएस)।

देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए कोयला और लिग्नाइट संसाधनों का तेज, अधिक कुशल और तकनीकी रूप से अन्वेषण आवश्यक है। कोयला मंत्रालय ऊर्जा की राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप, पारदर्शिता बढ़ाने, निजी क्षेत्र की भागीदारी को मजबूत करने और देश की ऊर्जा तैयारियों को सुदृढ़ करने हेतु प्रगतिशील सुधार लागू करता रहता है। यह पहल देश के लिए प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण और अन्वेषण इको सिस्टम को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करती है।

कोयला मंत्रालय ने पहले की कार्यप्रणाली की समीक्षा की है और वर्ष यूसीआई-एनएबीईटी तथा ऐसी ही किसी अन्य समीक्षित, अधिसूचित और मान्यता प्राप्त पूर्वेक्षण एजेंसियों (एपीए) द्वारा तैयार कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों के लिए अन्वेषण कार्यक्रमों और भूवैज्ञानिक रिपोर्टों (जीआरएस) के अनुमोदन हेतु प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। नई प्रक्रिया के लिए जनवरी 2022 में कोयला मंत्रालय की गठित समिति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। यह प्रमुख प्रक्रियात्मक सुधार अन्वेषण क्षेत्र में व्यापार सुगमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोयला मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नई कार्यप्रणाली इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

हाल ही में किए गए सुधारों में, मान्यता प्राप्त निजी पूर्वेक्षण एजेंसियों की क्षमताओं का विस्तार और उपयोग करके, सरकार ने निजी अन्वेषण संस्थाओं में विश्वास व्यक्त किया है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य देश के कोयला संसाधनों के सतत विकास के लिए उनकी दक्षता, तकनीकी विशेषज्ञता और नवाचार का उपयोग करना है, साथ ही पारदर्शिता और उच्च तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित करना है। भूवैज्ञानिक रिपोर्ट की अनुमोदन प्रक्रिया में कम से कम 3 महीने की बचत होगी, जिसके परिणामस्वरूप कोयला ब्लॉक का शीघ्र चालू हो सकेगा और कोयला ब्लॉक आवंटियों को समय पर लक्ष्य पूरे करने में सुविधा मिलेगी। इस सुधार से अन्वेषण में तेजी आने, अनुमोदन की समयसीमा कम होने और देश के कोयला संसाधनों की दीर्घकालिक सुरक्षा और सतत उपयोग में योगदान मिलने की उम्मीद है।

कोयला मंत्रालय ऐसे दूरदर्शी सुधारों के साथ, व्यापक ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश को सुदृढ़ बना रहा है। अन्वेषण क्षमताओं को मजबूत करके और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाकर, मंत्रालय एक सुदृढ़ कोयला इको सिस्टम में मदद कर रहा है जो आने वाले वर्षों में विकसित भारत की आकांक्षाओं को बल प्रदान करेगा और राष्ट्र के लिए एक अधिक मजबूत, भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा परिदृश्य का निर्माण करेगा।

चित्रनगरी संवाद मंच मुम्बई का मुशायरा

मुम्बई के रंगशारदा सभागार में आयोजित इंशाद के "नस्ल ए नौ भारत" मुशायरे का खुमार अभी उतरा भी नहीं था कि अगले दिन चित्रनगरी संवाद मंच में भी जोरदार मुशायरा हो गया। हँसी, ठहाकों और तालियों की गूंज के दौरान कुछ शायरों ने इतने उम्दा कलाम पढ़े कि सामयीन ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। इस धनक काव्य उत्सव में शामिल शायरों के नाम हैं - डॉ जुबैर अंसारी (लखनऊ), सुजीत सहगल 'हासिल'(धरमशाला), सोनू पाटिल (नागपुर), आशुतोष मिश्रा 'अजल' (दिल्ली), अलंकृत श्रीवास्तव (दिल्ली), हर्षल 'गाफिल' (पुणे), आयुष कश्यप (दिल्ली), कुमार कौशल (बरेली). इंशाद फाउंडेशन के प्रवर्तक नवीन जोशी 'नवा' के सान्निध्य में आयोजित इस काव्य संध्या का संचालन देवमणि पांडेय ने किया।

रविवार 30 नवम्बर 2025 को केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट गोरेगांव के मृणालताई हाल में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरूआत में अभिनेता

शैलेंद्र गौड़ की पत्नी प्रीति गीता गौड़ को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वरिष्ठ कवि प्रदीप गुप्ता ने प्रीति गौड़ को एक बेहतरीन उद्घोषक और सम्वेदनशील अभिनेत्री बताते हुए कहा कि प्रीति ने हंसते मुस्कुराते हुए कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का सामना किया। वह हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। वह हमारी स्मृतियों में हमेशा ज़िंदा रहेगी।

इस अवसर पर अभिनेत्री असीमा भट्ट के बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी दुआ की गई। कार्यक्रम में मशहूर शायर तनोज दाधीच (कोटा), नवील सैयद, तौसीफ कातिब, तारिक जमाल, जीशान साहिर, हेमंत शर्मा, प्रतिमा सिन्हा, पूनम विश्वकर्मा, मधुबाला शुक्ल, प्रज्ञा मिश्र, नाजनीन, हरगोविंद विश्वकर्मा, अनुज वर्मा, सुनील तिवारी, धर्मेंद्र कुमार मिश्र, शामी एम इरफान तथा कई और रचनाकार मौजूद थे।

दूरसंचार विभाग ने मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता जांचने के लिए उसमें संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करने के निर्देश जारी किए

- इंस्टॉल ऐप पहली बार ओपन करते समय उपयोगकताओं को दिखने चाहिए और वे सुगम तथा कार्य सक्षम होने चाहिए
- निमार्ताओं को सुनिश्चित करना होगा कि डिवाइस सेटअप के दौरान ऐप आसानी से सुलभ हो और इसके फीचर डिसेबल्ड या प्रतिबंधित न हो
- संबंधित अनुपालन रिपोर्ट 120 दिनों में देनी होगी

(जीएनएस)।

नकली मोबाइल हैंडसेट खरीदने से लोगों को बचाने, दूरसंचार संसाधनों के संदिग्ध इस्तेमाल की आसानी से सूचना देने और संचार साथी पहल प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए, दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार साइबर सुरक्षा प्रावधानों के तहत 28 नवम्बर, 2025 को निर्देश जारी कर देश में उपयोग के लिए मोबाइल हैंडसेट निमार्ताओं और आयातकों के लिए निम्नलिखित नियम अनिवार्य कर दिए हैं :

सुनिश्चित किया जाए कि देश में उपयोग के लिए निर्मित या आयातित सभी मोबाइल हैंडसेटों पर संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल हो।

सुनिश्चित किया जाए कि इंस्टॉल किए गए संचार साथी एप्लीकेशन उपयोगकताओं के उपयोग या डिवाइस सेटअप के समय आसानी से पूरी क्षमता और बिना किसी प्रतिबंध के उपलब्ध हों।

पहले से निर्मित ऐसे सभी उपकरणों और भारत में बिक्री हेतु मोबाइल हैंडसेट के निमार्ता और आयातक सॉफ्टवेयर अपडेट द्वारा इस ऐप का इस्तेमाल आगे बढ़ाने का प्रयास करें।

निदेर्शों में 90 दिनों में इसे कार्यान्वित करने और 120 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।

संचार साथी पहल : दूरसंचार विभाग ने साइबर धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग रोकने और दूरसंचार साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संचार साथी पहल शुरू की है। दूरसंचार विभाग ने संचार साथी पोर्टल और ऐप विकसित किया है जो लोगों को इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर के माध्यम से मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता जांचने में सक्षम बनाता है, साथ ही अन्य सुविधाएं जैसे संदिग्ध धोखाधड़ी संचार, खोए/चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट की रिपोर्ट करने, अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन की जांच करने, बैंकों/वित्तीय संस्थानों के विश्वसनीय संपर्क विवरण आदि की भी सहूलियत प्रदान करता है।

दूरसंचार सेवा नियमों के तहत केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या युक्त दूरसंचार उपकरणों के निमार्ताओं को छेड़छाड़ किए गए दूरसंचार उपकरणों या आईएमईआई संख्या से संबंधित निर्देश जारी करने का अधिकार है। इसमें यह अनिवार्य है कि निमार्ता या आयातक नियम प्रभावशीलता के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी निदेर्शों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

फर्जी या नकली आईएमईआई वाले मोबाइल हैंडसेट दूरसंचार साइबर सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन जाते हैं। दूरसंचार नेटवर्क में नकली/छेड़छाड़युक्त आईएमईआई के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां अलग-अलग स्थानों पर एक ही अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या युक्त अलग-अलग हैंडसेट सक्रिय होते हैं और इनके विरुद्ध कार्रवाई करना चुनौतीपूर्ण बन जाता है। भारत में सेकेंड-हैंड मोबाइल उपकरणों का बड़ा बाजार है। ऐसे मामले भी देखे गए हैं कि इनमें चोरी, गुमशुदा या ब्लैकलिस्ट किए गए उपकरण दोबारा बेचे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन मोबाइलों को खरीदने वाला भी अपराध में भागीदार बन जाता है और उसे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। ब्लॉक/प्रतिबंधित सूची में डाले गए आईएमईआई की जांच संचार साथी ऐप से की जा सकती है।

सांस्कृतिक धरोहर और संग्रहालयों का डिजिटलीकरण

सरकार सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, संग्रहालयों के डिजिटलीकरण और सांस्कृतिक प्रसार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संवर्धित वास्तविकता और अन्य उन्नत तकनीकों के उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। इनसे संबंधित विभिन्न पहलों में राष्ट्रीय संस्मारक एवं पुरावशेष मिशन (एनएमएमए), संग्रहालय डिजिटलीकरण पहल, वर्चुअल रियलिटी (वीआर) और संवर्धित वास्तविकता (एआर) आदि का उपयोग करके इमर्सिव विज़िटर एक्सपीरियंस शामिल हैं। पर्यटकों के देखने के अनुभव को बेहतर बनाने और इसे बढ़ाने के लिए संस्कृति मंत्रालय के तहत विभिन्न संग्रहालयों में एआर-वीआर, प्रोजेक्शन, डिजिटल कियोस्क आदि जैसी आधुनिक डिजिटल तकनीकों को अपनाया गया है। संस्कृति मंत्रालय अपने संग्रहालयों में प्रदर्शित विभिन्न कलाकृतियों के डिजिटलीकरण के लिए "जतन" नामक एक सॉफ्टवेयर का भी उपयोग कर रहा है।

अब तक राष्ट्रीय स्तर के 8 प्रसिद्ध संग्रहालयों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 2 संग्रहालयों को जतन सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटल किया गया है। अब तक डिजिटाइज की गई कलाकृतियों को सम्बंधित वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का उद्देश्य 'ट्यूलिप' के माध्यम से वंचित कारीगरों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने एवं विक्रय के लिए उन्हें ई-मार्केटिंग के माध्यम से एक वैश्विक मंच प्रदान करना है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अवस्थित खजुराहो में विंध्य क्षेत्र में एक पुरातत्व संग्रहालय का अनुरक्षण करता है। संग्रहालय को हाल ही में वर्ष 2023 में नई प्रदर्शन दीघाओं को जोड़ने और जनता के देखने के लिए और अधिक पुरावशेषों को शामिल करने के साथ उन्नत किया गया है।

यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

नवंबर माह में ऑपरेशन अमानत के तहत आरपीएफ द्वारा यात्रियों के 12 लाख रुपये से अधिक की कीमत के छूटे सामान को लौटाया गया

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल का रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहा है। सार्वजनिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखते हुए, वडोदरा मंडल के रेलवे सुरक्षा बल ने विभिन्न अभियानों के तहत नवम्बर ,2025 में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है।

मंडल के रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने "ऑपरेशन अमानत" के तहत, यात्रियों के 12 लाख रुपये से अधिक की कीमत के यात्रियों के कुल 83 छूटे हुए सामान को सफलतापूर्वक ढूंढकर उन्हें लौटा दिया।

वडोदरा मंडल के रेलवे सुरक्षा बल के रेलकर्मिओं द्वारा "आपरेशन दूसरा" के तहत बिना इजाजत के फेरी लगाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उनके खिलाफ बल के जवानों द्वारा रेगुलर ड्राइव जारी है। नवंबर महीने में चलाये गए इस अभियान में कुल 1184 बिना इजाजत फेरी लगाने वालों को गिरफ्तार किया गया और रेल अधिनियम 1989 की धारा के तहत उनका सामान जब्त किया गया। इसके अलावा, उन पर एक्सेस फेयर टिकट (EFT) लगाकर पेनल्टी लगाई गई। उनसे एक्सेस फेयर टिकट (EFT) राशि के तौर पर कुल 1,19,440 रुपये इकट्ठा किए गए।

रेलवे सुरक्षा बल के इन सतत प्रयासों ने न केवल रेलवे परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है, बल्कि यात्रियों में रेलवे के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना को भी सशक्त बनाया है।

आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने वर्मम थेरेपी का उपयोग करके उड़ान के दौरान त्वरित चिकित्सीय हस्तक्षेप करने वाले सिद्ध चिकित्सकों की सराहना की

(जीएनएस)।

आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने दो सिद्ध चिकित्सकों द्वारा हाल ही में एक उड़ान के दौरान एक सहयात्री को समयोचित चिकित्सीय सहायता प्रदान करने में दिखाए गए अनुकरणीय आचरण और नैदानिक कौशल की सराहना की है। श्री कोटेचा ने नई दिल्ली में डॉ. इलावरासन और डॉ. गौतम से मुलाकात की और वास्तविक जीवन की आपातकालीन स्थिति में उनकी सूझबूझ, जिम्मेदारी की भावना और सिद्ध वर्मम तकनीकों के प्रभावी उपयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से उन्हें धन्यवाद दिया।

उड़ान के दौरान एक यात्री को अचानक चक्कर आने लगे। हालाँकि, केबिन क्रू ने प्रारंभिक प्राथमिक उपचार प्रदान किया, लेकिन यात्री की हालत अस्थिर बनी रही, जिसके कारण चिकित्सा सहायता के लिए घोषणा की गई। तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सिद्ध चिकित्सक डॉ. इलावरासन और डॉ.गौतम ने यात्री की जांच की और शास्त्रीय सिद्ध लिटलेचर में वर्णित विशिष्ट वर्मम उत्पीडन तकनीकों का प्रयोग किया। कुछ ही मिनटों के भीतर यात्री को काफी राहत मिली, जिससे स्थिति को सुचारू रूप से स्थिर करने में मदद मिली।

आयुष मंत्रालय के सचिव ने डॉक्टरों के शांत, पेशेवर और करुणामय हस्तक्षेप की प्रशंसा की। उन्होंने जोर दिया कि ऐसी परिस्थितियों में सिद्ध वर्मम चिकित्सा का व्यावहारिक उपयोग प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा दिए जाने पर आपात स्थितियों में इसकी सहायक क्षमता को उजागर करता है। यह घटना स्वास्थ्य सेवा वितरण में उनकी व्यापक उपयोगिता बढ़ाने के लिए सिद्ध वर्मम तकनीकों के बारे में अधिक जन जागरूकता और संरचित प्रशिक्षण के महत्व को भी रेखांकित करती है।

एयर मार्शल तेजबीर सिंह ने महानिदेशक (निरीक्षण एवं सुरक्षा) के रूप में पदभार संभाला

(जीएनएस)।

एयर मार्शल तेजबीर सिंह ने 01 दिसंबर, 2025 को वायु सेना मुख्यालय में महानिदेशक (निरीक्षण और सुरक्षा) यानी डीजी (आई एंड एस) के रूप में पदभार ग्रहण किया।

वायु सेना अधिकारी ने अपने 37 वर्षों के शानदार करियर में, विभिन्न कमान और स्टाफ पदों पर कार्य किया है, जिनमें बांग्लादेश में हमारे एयर अटैची, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, नई दिल्ली में वरिष्ठ निर्देशन स्टाफ (वायुसेना) और वायु सेना मुख्यालय में सहायक वायु सेना संचालन प्रमुख (टी एंड एच) शामिल हैं। वे रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज, ब्रिटेन के पूर्व-छात्र हैं।

एयर मार्शल तेजबीर सिंह के पास व्यापक संचालन का अनुभव है और उनके नाम 7000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। वे भारतीय वायु सेना में सी-130जे 'सुपर हरक्यूलिस' विमान को शामिल करने और संयुक्त अभियानों के उद्देश्य से पहली 'स्पेशल ऑप्स' स्क्वाड्रन की स्थापना में अग्रणी रहे हैं। एयर ऑफिसर ने दो प्रमुख उड़ान अड्डों, एक प्रमुख प्रशिक्षण अड्डे और उत्तरी क्षेत्र को सहायता प्रदान करने वाले एक अग्रिम पंक्ति के परिचालन हवाई अड्डे की कमान संभाली है। मुख्यालय प्रशिक्षण कमान में वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी के रूप में अपने पिछले कार्यकाल में, उन्होंने प्रशिक्षण दर्शन को संचालन संबंधी उद्देश्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए एक रणनीतिक परिवर्तन का नेतृत्व किया।

एयर मार्शल तेजबीर सिंह को उनकी विशिष्ट सेवा के सम्मान में 2010 में वायु सेना पदक और 2018 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।

उन्होंने एयर मार्शल मकरंद भास्कर रानाडे का स्थान लिया, जो 39 वर्षों की विशिष्ट सेवा के बाद 30 नवंबर, 2025 को सेवानिवृत्त हुए।

रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में अनुसंधान और विकास

(जीएनएस)।

सरकार ने रक्षा विनिर्माण में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्न कदम उठाए हैं

निजी उद्योगों सहित विकास सह उत्पादन साझेदार (डीसीपीपी)/उत्पादन एजेंसी (पीए): रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को शामिल करते हुए प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से संभावित विनिर्माण एजेंसी की पहचान करने और उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विनिर्माण प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित करने के लिए डीसीपीपी मॉडल लागू किया है।

उद्योगों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी): डीआरडीओ ने उप-प्रणालियों, प्रणालियों और उपकरणों के निर्माण हेतु 2000 उद्योगों का एक समूह विकसित किया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रणालियों की प्रौद्योगिकी, विकास सह उत्पादन भागीदार (डीसीपीपी)/उत्पादन एजेंसी (पीए)/विकास भागीदार (डीपी) के लिए शून्य टीओटी शुल्क पर घरेलू उद्योगों को हस्तांतरित की जाती है। इन उद्योगों को डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

डीआरडीओ पेटेंट: भारतीय उद्योगों द्वारा डीआरडीओ पेटेंट के मुक्त क्षेत्र की नीति लागू की गई है।

प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ): रक्षा मंत्रालय की टीडीएफ योजना को डीआरडीओ द्वारा सार्वजनिक/निजी उद्योगों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई)/स्टार्ट-अप्स की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और मेक-इन-इंडिया पहल के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए क्रियान्वित किया जाता है। टीडीएफ के माध्यम से स्वीकृत परियोजनाओं को भी काफी सफलता मिली है, जिनमें से 26 प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया है और दो परियोजना प्रणालियों को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजा गया है। सरकारी आदेश के अनुरूप, डीप-टेक और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए टीडीएफ योजना के लिए 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई है।

नई स्टार्ट-अप नीति: डीआरडीओ इन उभरते स्टार्ट-अप्स के साथ संपर्क को सुगम बनाने के लिए एक नई नीति ला रहा है। इस नीति का उद्देश्य स्टार्ट-अप्स के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए उनके नवीन विचारों का लाभ उठाना है।

डेयर टू ड्रीम: चार डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी हैं। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य रक्षा और एयरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण करना है, जिसमें भविष्य में स्टार्ट-अप्स और व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों को अनुसंधान एवं विकास में शामिल करके भारतीय रक्षा और एयरोस्पेस आवश्यकताओं को अपनाने की अच्छी संभावनाएं हैं।

उद्योगों को परीक्षण सुविधा सहायता: डीआरडीओ प्रयोगशालाओं में कई विश्व स्तरीय अनुसंधान एवं विकास परीक्षण सुविधाएं अब उद्योगों के लिए उपलब्ध हैं और इनके लिए आवश्यक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार कर ली गई है। डीआरडीओ की 24 प्रयोगशालाओं की परीक्षण सुविधाओं को रक्षा परीक्षण पोर्टल (डीटीपी) पर अपलोड कर दिया गया है। यह पोर्टल मंत्रालय की परीक्षण अवसंरचना रक्षा उद्योगों को पारदर्शी ढंग से उपलब्ध कराता है।

उद्योगों के साथ संपर्क: उद्योगों की सुविधा के लिए प्रयोगशालाओं में उद्योग संपर्क समूह (आईआईजी) स्थापित किए गए हैं।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25 प्रतिशत उद्योग, स्टार्ट-अप और शिक्षा जगत के लिए खोला गया: वर्ष 2022-23 की बजट घोषणाओं के आधार पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25 प्रतिशत उद्योग, स्टार्ट-अप और शिक्षा जगत के लिए खोल दिया गया है।

बा' अनुसंधान: बा' अनुसंधान का उद्देश्य महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में आवश्यक ज्ञान और क्षमताओं का विकास करना, शोधकर्ताओं के साथ संपर्क स्थापित करना, कुशल मानव संसाधन विकसित करना और देश में विकसित हो रहे रक्षा अनुसंधान एवं विकास इको सिस्टम का समर्थन करने के लिए भारतीय शैक्षणिक संस्थानों/अनुसंधान केंद्रों में अनुसंधान अवसंरचना को बढ़ावा देना है।

डीआरडीओ-उद्योग-अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र (डीआईए-सीओई): डीआरडीओ के पास डीआरडीओ उद्योग-अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र (डीआईए-सीओई) के एक नेटवर्क के माध्यम से रक्षा और सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण और भविष्योन्मुखी प्रौद्योगिकियों के विकास में सहयोगात्मक निर्देशित अनुसंधान हेतु नीति और तंत्र मौजूद है। इसके तहत कुल 15 डीआईए-सीओई स्थापित किए गए हैं जो लगभग 82 चिन्हित अनुसंधान क्षेत्रों में अनुवादात्मक अनुसंधान गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं।

रक्षा उद्योग गलियारे: डीआरडीओ उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे को ज्ञान भागीदार के रूप में उद्योगों के साथ सहयोग करके सहायता प्रदान कर रहा है। इन गलियारों की स्थापना 'आत्मनिर्भरता' प्राप्त करने और 'मेक इन इंडिया' के लक्ष्य को साकार करने के लिए की गई है।

रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईडीईएक्स): माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अप्रैल 2018 को रक्षा के लिए नवाचार इको सिस्टम आईडीईएक्स की शुरूआत की थी। इसका उद्देश्य स्टार्ट-अप्स/एमएसएमई/व्यक्तिगत इनोवेटर्स, अनुसंधान और विकास संस्थानों और शिक्षाविदों सहित उद्योगों को शामिल करके रक्षा और एयरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है।

सित्तनवसल का ऐतिहासिक महत्व

(जीएनएस)।

सित्तनवसल, तमिलनाडु के पुदुक्कोट्टई जिले के विरालिमलाई विधानसभा क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख और रखरखाव के तहत राष्ट्रीय महत्व का एक स्मारक है। इसका ऐतिहासिक और पुरातत्विक महत्व बहुत अधिक है। इसमें जैन तपस्वियों के पत्थर के बिस्तर और तमिल-ब्राह्मी शिलालेखों वाला शैलाश्रय, 7वीं-9वीं सदी में चट्टान को काटकर बनाया गया गुफा मंदिर जिसमें शुरूआती दुर्लभ भित्ति चित्र इत्यादि शामिल हैं, जो आरंभिक जैन चरित्रों और पुरानी कला परंपराओं को दशार्ते हैं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सित्तनवसल स्मारकों के संरक्षण, अनुसंधान और संवर्धन के लिए लगातार कदम उठाए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आवश्यकतानुसार विशेष मरम्मत कार्यों, वार्षिक रखरखाव और अनुरक्षण के माध्यम से इनका संरक्षण सुनिश्चित करता है। ये भित्ति-चित्र भलि-भांति परिरक्षित हैं। इसके अलावा, मंडल कार्यालय द्वारा स्थानीय जनता और छात्रों को शामिल करके स्मृति धरोहर की बेहतर समझ और इसके प्रचार के लिए सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

वर्तमान में, सित्तनवसल में अतिरिक्त अवसंरचना विकास का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस स्थल में पहले से ही बुनियादी पर्यटक सुविधाएं जैसे शौचालय, पेयजल, क्यूआर-कोड आधारित संकेतक, सांस्कृतिक और स्मारक सुरक्षा सूचना बोर्ड, पत्थर की बेंच, प्रकाशन काउंटर, गाड़ी योग्य सड़क आदि है।

यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

राष्ट्रपति ने फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया

(जीएनएस)।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (1 दिसंबर, 2025) नई दिल्ली में फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में

कहा कि भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है और वैश्विक आर्थिक मंच पर आर्थिक भूमिका विस्तारित करने में सक्षम है। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत फुटवियर क्षेत्र को 'चैंपियन सेक्टर' का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार फुटवियर क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के साथ ही प्रोत्साहन दे रही है।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत फुटवियर उत्पादन और इसके खपत के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का फुटवियर निर्यात 2500 मिलियन डॉलर से कुछ अधिक था जबकि इसका आयात लगभग 680 मिलियन डॉलर था। इसे देखते हुए भारत का फुटवियर निर्यात आयात का लगभग चार गुना है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में फुटवियर का प्रमुख निर्यातक है पर इसे और बढ़ाने के लिए फुटवियर व्यवसाय का विस्तार जरूरी है जिससे इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को उद्यम स्थापित कर रोजगार सृजन या उद्यमों में रोजगार पाने के अवसर बढ़ेंगे।

राष्ट्रपति ने फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और नॉर्थम्प्टन विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हर्ष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इससे भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत सहयोग और गहन होगा। उन्होंने रेखांकित कि यह समझौता ज्ञापन टिकाऊ सामग्रियों और चक्रीय अर्थव्यवस्था पर विशेष जोर देता है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास पर्यावरण संरक्षण के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता दशार्ते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि फुटवियर डिजाइन के क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। उन्होंने स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपने कार्यों द्वारा समाज और देश के लिए बहुमुखी योगदान देने के व्यापक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे फुटवियर डिजाइन से लोगों के स्वास्थ्य और उपादेयता, कार्यक्षमता में सुधार, अपने कार्य द्वारा लोगों के लिए रोजगार सृजित करने, अपेक्षाकृत पीछे रह गए लोगों को आर्थिक विकास में भागीदार बनाने, भारत के निर्यात में योगदान देकर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, गुणवत्तापूर्ण उत्पादों द्वारा वैश्विक बाजार में भारत को ब्रांड एंबेसडर बनाने और 'आत्मनिर्भर भारत' के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में अपना योगदान देने की हेतु कार्य करें।

एनसीपीओआर भारत के ध्रुवीय और महासागरीय अन्वेषण का आधार बन गया है: गोवा के राज्यपाल

संस्थान की रजत जयंती के उपलक्ष्य में विशेष स्मृति डाक टिकट जारी किया गया

प्रविष्टि तिथिः 01 अ्रउ 2025 5:59ढट८ ढक्ह ऊ

गोवा के राज्यपाल श्री पुसापति अशोक गजपति राजू ने आज (1 दिसम्बर 2025) वास्कोडिगामा में एनसीपीओआर परिसर में अंटार्कटिका दिवस सहारोह में बोलते हुए कहा कि राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र भारत के ध्रुवीय और महासागरीय अन्वेषण का आधार बन गया है। अंटार्कटिका संधि पर 1 दिसम्बर 1959 को हस्तक्षर किए जाने की याद में दुनियाभर में अंटार्कटिका दिवस मनाया जाता है। यह संधि अंटार्कटिका महाद्वीप को पूर्णतः शांति और वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु सुरक्षित घोषित करती है।

राज्यपाल, जो इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, ने एनसीपीओआर की स्थापना की रजत जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष स्मृति डाक टिकट भी जारी किया।

राज्यपाल ने कहा कि केन्द्र सरकार के डाक विभाग द्वारा स्मृति डाक टिकट जारी करना एनसीपीओआर के उल्लेखनीय योगदान और 5 अप्रैल 2000 को अपनी स्थापना के बाद से ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान में राष्ट्र को समर्पित 25 वर्षों की गौरवशाली सेवा की एक महत्वपूर्ण स्वीकृति है।

उन्होंने कहा, "इस संस्थान ने 25 वर्षों से हमारी पृथ्वी के कुछ सबसे असाधारण क्षेत्रों में भारत की वैज्ञानिक कल्पना का विस्तार किया है। एनसीपीओआर ने गहरे महासागर मिशन का नेतृत्व भी किया है। यह उस विचार को आगे बढ़ाता है जो ज्ञान का एक साधन और राष्ट्रीय रणनीति का एक उपकरण दोनों है। ध्रुवीय क्षेत्र दूर लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव हम सभी पर पड़ता है।

नमो घाट पर इंस्टॉलेशन आर्ट प्रतियोगिता, छात्रों द्वारा बनाए आर्ट कृतियों में दिखा काशी और तमिल संस्कृति का अनोखा संगम

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के अंतर्गत काशी तमिल संगमम्-4.0 का आयोजन 2 दिसंबर से वाराणसी में होने जा रहा है। यह पूरा आयोजन शिक्षा मंत्रालय की देखरेख में हो रहा है। वाराणसी में इस आयोजन की मेजबानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही है। आयोजन से पहले कई कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा रहा है।

इसी क्रम में नमो घाट के पावन तट पर 'इंस्टॉलेशन आर्ट प्रतियोगिता-2025' का भव्य आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य काशी और तमिलनाडु की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना था। लर्न तमिल थीम पर आधारित इस प्रतियोगिता में बीएचयू सहित अन्य कॉलेज के 50 से अधिक स्टूडेंट्स ने भाग लिया। प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चली। जिसमें प्रतिभागियों ने व्यक्तिगत तथा समूह दोनों रूपों में भाग लिया। इस आयोजन में प्रस्तुत इंस्टॉलेशन आर्ट कृतियों में मंदिर स्थापत्य, द्रविड़ एवं नागर शैली की झलक, काशी की

गलियों की जीवंतता, काशी विश्वनाथ मंदिर के आध्यात्मिक दृश्यों, नटराज की गतिमय आकृति तथा तमिलनाडु के पारंपरिक नृत्य-संगीत तत्वों को दशार्या गया। कलाकारों ने लकड़ी, मिट्टी, कपड़े, धातु, लालटेन, जूट और पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग करते हुए सांस्कृतिक एकता और परंपराओं के गहरे संबंध को रचनात्मक रूप से व्यक्त किया।

कार्यक्रम के समन्वयक, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स के सहायक प्रोफेसर साहेब राम तुडु और डॉ. आशीष कुमार गुप्ता ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों को न केवल कलात्मक स्वतंत्रता देना है बल्कि उन्हें भारतीय सांस्कृतिक विविधताओं को अनुभवात्मक रूप से समझने का अवसर प्रदान करना भी है। उनका कहना कि काशी और तमिलनाडु का ऐतिहासिक व आध्यात्मिक रिश्ता कला के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुँचाया जाना आवश्यक है। स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों ने भी बड़ी संख्या में पहुँचकर इस सांस्कृतिक कला-उत्सव का आनंद लिया। नमो घाट की सुंदरता और कलाकारों की रचनात्मक अभिव्यक्तियों ने इसे एक यादगार आयोजन बना दिया। कार्यक्रम की सफलता ने सिद्ध कर दिया कि कला दो संस्कृतियों के बीच सेतु का कार्य करते हुए एकता, सौहार्द और परंपरा के साझा धागों को और अधिक मजबूती देती है।

काशी तमिल संगमम्-4.0 के अंतर्गत वसंत कॉलेज में प्रमोशनल अकादमिक गतिविधियों की शुरूआत

(जीएनएस)।

काशी तमिल संगमम् 4.0 के अंतर्गत वसंत कॉलेज फॉर वीमेन,वाराणसी में 26 नवंबर 2025 से प्रमोशनल अकादमिक गतिविधियों की श्रृंखला आरंभ हुई। जिसका उद्देश्य काशी और तमिलनाडु के सहस्राब्दियों से चले आ रहे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं भाषाई संबंधों को नई ऊर्जा प्रदान करना है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार की सहभागिता में और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के समन्वय से आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन डॉ. जी. थवासी मुरुगन द्वारा किया गया।

प्रथम दिवस पर आयोजित विशेष व्याख्यान सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित डॉ. जगदीशन टी., सहायक प्रोफेसर (भारतीय भाषाएँ) एवं कोर कमेटी सदस्य, ङ्ळर ने 'तमिल करकलाम' अर्थात तमिल शिक्षण को इस वर्ष के संगमम् की मूल थीम बताते हुए कहा कि तमिल भाषा केवल एक भाषा ही नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की प्राचीनतम और समृद्ध ज्ञान-धरोहरों में से एक है। उन्होंने कहा कि काशी और तमिलनाडु का आध्यात्मिक संबंध अत्यंत पुराना है, जो तीर्थ, परंपरा, साहित्य, संगीत, स्थापत्य और दर्शन के माध्यम से दोनों क्षेत्रों को अविच्छिन्न रूप से जोड़ता है। तमिल संतों और विद्वानों की काशी यात्राओं ने यहाँ की सांस्कृतिक चेतना को निरंतर समृद्ध किया है, जिससे यह संबंध और अधिक प्रगाढ़ हुआ है।

उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया कि भारत की भाषाई विविधता उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और भारतीय भाषाओं का अध्ययन न केवल हमारी पहचान को सुदृढ़ करता है, बल्कि ज्ञान और रोजगार के अवसरों का विस्तार भी करता है।

विश्व एड्स दिवस, डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई

सीएमओ आलोक कुमार के नेतृत्व में स्कूली बच्चों ने बैनर थामे संदेश दिया – पुलिस सुरक्षा में मुख्य मार्गों से गुजरी, भेदभाव मिटाने व फ्री जांच की अपील

(जीएनएस)।पीलीभीत, 1 दिसंबर आज विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर से इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (उटड) आलोक कुमार के निर्देश पर निकाली गई यह रैली ल्क्ष्य/एड्स के प्रति जनता को जागरूक करने और इससे जुड़े सामाजिक कलंक को दूर करने का प्रमुख माध्यम बनी। शहर भर में सकारात्मक माहौल छाया रहा, जहां सैकड़ों लोग शामिल हुए।

रैली का पूरा विवरण:

रैली कलेक्ट्रेट से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों – स्टेशन रोड, सदर बाजार और गणेश गंज होते हुए वापस कलेक्ट्रेट पर समाप्त हुई। उटड आलोक कुमार के आह्वान पर विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। उनके हाथों में रंग-बिरंगे बैनर और तख्तियां थीं, जिन पर लिखा था – "एड्स से बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है", "संक्रमितों के साथ भेदभाव न करें, समान व्यवहार करें", "जागरूक रहें, स्वस्थ रहें"। बच्चों के उत्साहपूर्ण नारों ने राहगीरों का ध्यान खींचा और कई दुकानदार व स्थानीय लोग भी रुककर संदेश को समझा। रैली के दौरान कोई अव्यवस्था न हो, इसके लिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया। ट्रैफिक पुलिस ने मार्ग सुचारू रखा, वाहनों को वैकल्पिक रूट दिए।

DM व CMO की अपील:

जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाते हुए कहा, "एड्स के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता ही सबसे मजबूत हथियार है। हमें सही जानकारी फैलानी चाहिए और संक्रमित लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबको समान अधिकार हैं।" उन्होंने सभी नागरिकों से एचआईवी जांच कराने और सुरक्षित जीवनशैली अपनाने की सलाह दी। CMO आलोक कुमार ने बताया कि जिले के सभी सेहत केंद्रों व अस्पतालों पर निशुल्क ल्क्ष जांच, काउंसलिंग और दवाओं की सुविधा उपलब्ध है। "कोई शर्म न करें, समय पर जांच से जीवन बचाया जा सकता है।" उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर कई अन्य कार्यक्रम जैसे सेमिनार व कैंप भी चल रहे हैं।

प्रभाव व पृष्ठभूमि:

यह रैली विश्व एड्स दिवस की थीम "Let Communities Lead" के अनुरूप थी, जो समुदाय की भूमिका पर जोर देती है। पीलीभीत में एड्स प्रभावितों की संख्या नियंत्रण में है, लेकिन जागरूकता से इसे और कम किया जा सकता है। स्थानीय लोगों ने रैली की सराहना की – "बच्चों का जोश देखकर अच्छा लगा, संदेश घर-घर पहुंचेगा।" स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में गांव-गांव में अभियान चलाएंगे।

राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत से मोहित हिंदू में काफी शोक संवेदना

(जीएनएस)।

मसौली बाराबंकी आपको बता दे पूरा मामला वन रेंज व थाना मसौली जनपद बाराबंकी जनपद बाराबंकी के मोहल्ला भूलीगंज स्थित डॉ रोहित के खेत में सागौन की बाग लगी हुई है उसी में एक राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हुई है इसके बाद मौके पर पहुंचकर इस बात की सूचना क्षेत्राधिकार व वन दरोगा सतीश मिश्रा को दिया इसके बाद एक-एक करके काफी ग्रामीण एकत्रित हो गए घंटों इंतजार के बाद वन विभाग की टीम देर से पहुंचने पर

ग्रामीणों में काफी आक्रोश व बिना किट के राष्ट्रीय पक्षी मोर को एक बोरी में लपेटकर ले जाने को लेकर मुंह पर तमाचे जैसा लगा इसके बाद वन विभाग की टीम पोस्टमार्टम के लिए ले गई जिसमें हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जिला प्रभारी (छोटा योगी) मोहित हिंदू ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद सिद्ध हो पाएगा कि किस कारण राष्ट्रीय पक्षी मोर मौत हुई है उसके बाद ही दाह संस्कार सा सम्मान किया जाएगा इस मौके पर जितेंद्र वर्मा शुभम वर्मा किसान नेता राहुल गुप्ता सहित कई क्षेत्रीय ग्रामीण उपस्थित रहे।।

जर्जर सड़कों पर भड़का आक्रोश, विधायक राज सिन्हा का अनिश्चितकालीन धरना शुरू, 48 घंटे का अल्टीमेटम

(जीएनएस)।

धनबाद : शहर की जर्जर सड़कों का निर्माण,नालियों के निर्माण, विभिन्न वार्डों में स्ट्रीट लाइट, यूजर चार्ज और टैक्स देने के बाद भी धनबाद की आम जनता के कार्य नहीं होने के विरोध में, अविलंब निर्माण की मांग को लेकर आज धनबाद में आक्रोश खुलकर सामने आया। झारखंड विधानसभा के सचेतक सह धनबाद विधायक राज सिन्हा ने नगर निगम मुख्यालय के सामने प्रभावित आमलोगों,समर्थकों और सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अनिश्चितकालीन धरने की शुरूआत की।

सुबह से ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और नगर प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। धरना स्थल पर विधायक ने स्पष्ट चेतावनी दी— '48 घंटे के भीतर अगर सड़क मरम्मत पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं नगर निगम कार्यालय की चौखट पर धरना दूंगा। आगे स्थिति यथावत रही तो नगर आयुक्त के चैंबर के बाहर भी आमरण आंदोलन करेंगे।'

उन्होंने आरोप लगाया कि बीते छह वर्षों से सड़क निर्माण की लगातार मांग की जा रही है, परंतु हर बार नगर निगम और राज्य सरकार अउइ जांच का हवाला देकर फाइल दबा देती है।

विधायक ने कहा—

'टूटी-फूटी सड़कें जनता के जीवन को नरक बना चुकी हैं। बरसात में हालात जानलेवा हो जाते हैं, मगर सरकार चुप है।'

उन्होंने धनबाद की प्रमुख सड़कों— बरटांड़ पंडित क्लीनिक-रोड, राजकीय पॉलीटेक्निक-पांडरपाला मार्ग, गांधी नगर रोड, सब्जी बगान रोड, डीएस कॉलोनी रोड, माडा कॉलोनी रोड, विनोद नगर, मनईटांड़, गोल बिल्डिंग-छठ तालाब-भोक्ता मेला मार्ग, पथराकुल्ही रोड—पर तत्काल कार्य शुरू कराने की मांग की।

धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महानगर जिला अध्यक्ष श्रवण राय ने कहा—

'पूरा धनबाद विकास कार्यों के ठप होने से परेशान है। नगर निगम की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।'

नेताओं के वक्तव्य

जिला महामंत्री मानस प्रसून ने कहा कि, 'नगर निगम धनबाद की जनता का टैक्स लेता है, लेकिन सुविधा देने में नाकाम साबित हुआ है। अब भाजपा सड़क पर है— जब तक समाधान नहीं, संघर्ष जारी रहेगा।'

प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राजकुमार अग्रवाल 'धनबाद को स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया गया, मगर सच्चाई यह है कि सड़कें मौके पर गड्ढों में तब्दील हैं। जनता का सब्र टूट रहा है, इसलिए भाजपा उनकी आवाज बनकर खड़ी है।'

जिला मंत्री सह मीडिया प्रभारी पंकज सिन्हा 'विधायक राज सिन्हा लगातार इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष, नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू के समक्ष, धनबाद उपायुक्त सहित एसीबी के तत्कालीन राज्य प्रमुख अनुराग गुप्ता सहित सभी संबंधित विभागों में लिखित एवं मिलकर भी आमलोगों को होने वाली कठिनाइयों से अवगत करा चुके है। झारखंड विधानसभा में भी कई बार इस जनहित के कार्य पे प्रश्न किया मामले को जोरदार तरीके से उठा चुके है। लड़ाई लड़ रहे हैं, पर सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। विधायक श्री सिन्हा ने कहा कि,

जनता के हित में यह आंदोलन और आक्रामक रूप लेगा, अगर सड़क निर्माण कार्य, नाली निर्माण कार्य, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य विकास कार्य पर तुरंत कार्य नहीं हुआ।' तो

विधायक राज सिन्हा ने कहा—

स्पष्ट रोडमैप और लिखित कार्ययोजना आने तक धरना अनवरत जारी रहेगा। संध्या बेला में नगर निगम के उप नगर आयुक्त प्रकाश कुमार विधायक राज सिन्हा को मनाने धरना स्थल पे निगम के अन्य पदाधिकारियों के साथ आए। परंतु विधायक श्री सिन्हा ने स्पष्ट रूप से कार्य शुरू नहीं तक धरना जारी रखने की बात कही।

आज के अनिश्चितकालीन धरना के पहले दिन मुख्य रूप से संबोधित करने वालों में निवर्तमान वार्ड पार्षद अशोक पाल, मनोरंजन सिंह, मुखिया रमेशधनबाद — सिंह,जिला मंत्री नरेंद्र त्रिवेदी, जिला मंत्री रीता यादव, साहू समाज के युवा अध्यक्ष विकास साव, सुमन सिंह अभिमन्यु कुमार, अमरजीत कुमार, रणविजय सिंह, सोनी सिंह, पुष्पा राय,महिला मोर्चा की अध्यक्ष विभा रानी सिंह, भाजयुमो अध्यक्ष नित्यानंद मंडल, मंडल अध्यक्ष राजकुमार मंडल, संजय कुशवाहा, राजाराम दत्ता, योगेन्द्र यादव, पूर्व मुखिया दीपक सिंह चौधरी, कैलाश गुप्ता , विकास मिश्रा,सुमन सिंह, मौसम सिंह , कपिलदेव पासवान, गीता सिंह, श्यामल राहा, हुलास दास, राणा सिंह, मनोज रिंकू, राजकुमार मंडल, कमल सिंह, बालमुकुंद राम, जितेंद्र कुमार, अनिल खेमका, चुना सिंह, बबलू फरीदी, आनंद खंडेलवाल, तमाल राय, अनिल सिन्हा, सतीश रजक, सत्येंद्र ओझा, सुप्रभात कुमार, सरोज शुक्ला, मदन तिवारी, श्याम गुप्ता, मेघनाथ वर्मा, पूर्व मुखिया छोटू दास, ओमप्रकाश झा, इंद्रकांत झा, प्रयाग रविदास, राहुल सिंह, बबलू सिंह, पप्पू शर्मा, सपन कश्यप, विकास सिंह, अनुपम शरण, मिथुन ठाकुर, अजय मालाकार, उमेश यादव सहित हजारों आम लोग उपस्थित थे।

किशोरी पर रिश्तेदारों का बेरहमी से हमला, शौचालय विवाद में बांका से वार

(जीएनएस)।

पीलीभीत,1 दिसंबर जहानाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम गहलुईया में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। 15 साल की किशोरी पर रिश्तेदारों ने शौचालय के विवाद में बेरहमी से हमला किया। 23 नवंबर रात 12 बजे भागवत कार्यक्रम से लौटी किशोरी बाहर शौचालय जा रही थी, तभी रिश्तेदार हरेंद्र व पत्नी शगुन देवी

ने विरोध शुरू कर गाली-गलौज की। प्रतिरोध पर हरेंद्र ने बांका से वार कर गंभीर घायल किया।

घटना विवरण:

चीखें सुन परिवार पहुंचा, आरोपी धमकी देकर भागे। मां कमलेश कुमारी (पत्नी हरनाम सिंह) की तहरीर पर थाना प्रभारी प्रदीप विश्नोई ने मुकदमा दर्ज – IPC 323, 504, 506, 326। घायल को अस्पताल में भर्ती। प्रभारी बोले,गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।"

टाइगर रिजर्व : बाघिन शावकों संग सड़क पर टहलावट से टूरिस्ट दहशत में

10 मिनट ट्रैफिक जाम – वीडियो वायरल, रिजर्व 15 दिन पहले खुला, चूका बीच 'मिनी गोवा' पर रिकॉर्ड बुकिंग, 80 बाघ व 326 पक्षी प्रजातियां

(जीएनएस)।

पीलीभीत, 1 दिसंबर पीलीभीत टाइगर रिजर्व (ढळफ) में रविवार को एक रोमांचक नजारा देखने को मिला। खटीमा मार्ग पर लाल पुल के पास एक बाघिन अपने दो शावकों के साथ सड़क पर टहलने लगी। टूरिस्टों को देखते ही सब सहम गए – गाड़ियां रुक गईं, करीब 10 मिनट तक दोनों तरफ ट्रैफिक जाम। चुपचाप खड़े

होकर लोग वीडियो बनाते रहे, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। वन विभाग ने कहा, "प्रकृति का कमाल, लेकिन सतर्क रहें।"

घटना का पूरा विवरण:

बाघिन व शावक सड़क पर चहलकदमी करते रहे, टूरिस्ट उत्साहित लेकिन डरे। ढळफ 15 जून से मानसून में बंद रहता, लेकिन इस बार बढ़ती मांग पर 15 दिन पहले खोल दिया। रिकॉर्ड एडवांस बुकिंग – खासकर चूका बीच, जो 'मिनी गोवा' कहलाता। यहां वाटर फ्रंट व्यू, बैंबू हट्स, बोट सफारी ने पर्यटकों को दीवाना बना दिया। 9 नवंबर तक हट्स (बैंबू, थारू, ट्री) फुल बुक, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी का स्वर्ग। ढळफ ने टाइगर संख्या बढ़ाने पर अवॉर्ड भी जीता।

रिजर्व की खासियतें:

72,689 हेक्टेयर (730 वर्ग किमी) में फैला ढळफ – 80 बाघ, तेंदुए, भालू, हिरण व 326+ पक्षी प्रजातियां। उत्तर में नेपाल बॉर्डर, दक्षिण में शारदा-खकरा नदियां, पूर्व-पश्चिम घने जंगल। आकर्षण: जंगल-बोट सफारी, कैंपिंग, शारदा सागर डैम व्यू, सप्त सरोवर ट्रेल। बराही-महोफ रेंज बाघ व बड्र्स के लिए बेस्ट। बिग कैट व बर्ड लवर्स के लिए जन्नत।

वन अधिकारी बोले, "टूरिज्म बूस्ट, लेकिन नियम पालन जरूरी।"

लखन लाल मिश्र के पुत्री के वैवाहिक समारोह में पहुँचे प्रयागराज कॉउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव

(जीएनएस)।

लखनऊ। अनंदा वेडिंग रिजॉर्ट ग्रीन कॉरिडोर लखनऊ में पत्रकार विकास कॉउंसिल भारत के राष्ट्रीय संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार मान्यता प्राप्त लखन लाल मिश्र के पुत्री के वैवाहिक समारोह में पहुँचे कॉउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव डीके मिश्र बीएचयू चिकित्सा विज्ञान संस्थान आईएमएस के निदेशक प्रो. एस एन संखवार, किसान मोर्चा प्रदेश कार्यालय प्रभारी आचार्य कुशमुनि स्वरूप, वरिष्ठ पत्रकार शेखर पंडित, राकेश वर्मा, सुरेश यादव, अनिल वर्मा, के के साहनी, तरुण चतुवेर्दी, वीरेंद्र सिंह, राकेश तिवारी, नीरज महेरे, एके सेंगर, डॉ० जे एस शुक्ला पीजीआई, सौरभ द्विवेदी कानपुर मंडल प्रभारी, आशीष मिश्र प्रयागराज मंडल प्रभारी, संदीप सिंह, मोहम्मद सरीफ, मोहम्मद इरफान, सौरभ तिवारी, गुडडू खान सहित बड़ी संख्या में साथी उपस्थित रहे।

व्यापारी पूरनलाल राठौर का बांद्रा टर्मिनस से लापता मामला गहराया

10 नवंबर से गायब, मोटरसाइकिल जब्त, गोडाउन में माल पड़ा, परिजनों ने CM से मदद मांगी – कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, अपहरण की आशंका

(जीएनएस)।

पीलीभीत, 1 दिसंबर सुखदासपुर नरोलिया गांव के 45 वर्षीय व्यापारी पूरनलाल राठौर 10 नवंबर से रहस्यमय ढंग से लापता हैं। 3 नवंबर को 7 क्विंटल गुड़-चावल का माल लादकर अपनी लूना मोटरसाइकिल (UP26Z-4534) से बांद्रा टर्मिनस गए थे। 4 नवंबर को माल गोडाउन में उतारा, मुंबई के कल्याण रिश्तेदारों के पास रुके। 10 नवंबर को "माल बेचकर लौटूंगा" कहकर निकले, उसके बाद मोबाइल बंद, कोई सुराग नहीं। जोगेश्वरी ट्रैफिक पुलिस को उनकी बाइक जब्त मिली।

परिजनों की शिकायत:

छोटे भाई शंकर लाल राठौर ने मुंबई पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई न होने पर पीलीभीत कलेक्ट्रेट पर ग्रामीणों संग प्रदर्शन। CM योगी को ज्ञापन SDM को सौंपा – महाराष्ट्र सरकार से मदद की गुहार। शंकर बोले, "गोडाउन फुटेज में पूरनलाल परेशान दिखे, अधिकारियों-व्यापारियों से माल को लेकर बहस। धमकी मिली – 'कोर्ट जाओ'। माल अभी भी गोडाउन में, अपहरण या अनहोनी की आशंका।" परिवार चेतावनी – FIR, हाई-लेवल जांच, सुरक्षित बरामदगी, वरना जिम्मेदार बांद्रा वाले।

पुलिस की अपील:

मुंबई पुलिस जांच कर रही, लेकिन ठोस क्लू न। पीलीभीत SP ने कहा, "समन्वय से तलाश तेज।"

एक अनसुलझा सवाल!

परवेज अख़्तर

आज तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है,

पर हम अभी भी कागजों के मकड़जाल में फँसे हुए हैं।

आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बिजली स्मार्ट कार्ड,जॉब कार्ड, इसके अलावा आयुष्मान कार्ड और हर सरकारी योजना के अलग अलग कार्ड।

साथ ही जन्म प्रमाण पत्र,

आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र,

निवास प्रमाण पत्र,

पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, तथा बैंक की के.वाई.सी, अलग से।

हमारा देश आज भी "कागज" और "कार्ड" की व्यवस्था में पूरी तरह उलझा हुआ है।

आधा साल "कागज" बनाने में और आधा साल कागज में "संशोधन" कराने में बीतता है।

संबंधित अधिकारियों के पास काम कम है,

पर उनकी टेबल और अलमारी में फाइलें ज्यादा हैं, जिसमें अधिकारी और नागरिक पूरी तरह उलझे हुए हैं।

जिस कारण तमाम नागरिक अपने "उलझे" हुए जरूरी काम भी "सुलझा" नहीं पा रहे हैं।

कई देशों में एक कार्ड के एक क्लिक में कार्ड धारक की पूरी अपडेट्स दिख जाती है।

इतनी उन्नति के बाद आखिर हमारे यहां

"एक शख़्स एक कार्ड " की व्यवस्था क्यों नहीं लागू हो पा रही है ??

पन्द्रह लाख का ठेका, आम जनता से वसूली हसनगंज पुलिस बनी मूकदर्शक

(जीएनएस)।

लखनऊ। आपको बताते चलें हसनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कतकी मेला में सड़क बनी अवैध पार्किंग का अड्डा सड़क पर पार्किंग होने की वजह से आवागमन में लोगों को हो रही है परेशानी मेला संचालक सनी गुप्ता के इशारे पर सड़क पर लगाई जा रही है पार्किंग नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा है मेला समिति के नाम पर हो रही है जमकर उगाई नगर निगम के नए मानकों के विपरीत जमकर हो रही है धन उगाही स्कूटर/मोटरसाइकिल की ₹10 कि दर तय है इसके विपरीत 30 रुपये में प्रति गाड़ी ले रही है ठेकेदार के गुर्गे कारों से भी ₹30 की जगह ₹100 की वसूली की जा रही है पूछने पर बताया 3 लाख रुपए का ठेका इस बार 15 लाख का हुआ है कहां से पैसा वसूला जायेगा पुलिस का भी हिस्सा तय हसनगंज पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है नंगा नाच हसनगंज पुलिस व चौकी इंचार्ज की वसूली में है मौन

स्वीकृति धारण किए नजर आ रहे है

रेहड़िया पुलिस चौकी पर होमगार्ड रामकिशोर का रिटायरमेंट विदाई समारोह बड़े ही धूमधाम से किया गया

बदायूं रेहड़िया पुलिस चौकी पर होमगार्ड रामकिशोर निवासी ग्राम खुर्रामपुर भमोरी का रिटायरमेंट विदाई समारोह रेहड़िया पुलिस चौकी इंचार्ज मनोज कुमार एवं होमगार्ड दरोगा महिपाल के नेतृत्व में किया गया बता दें कि 60 वर्ष पूरे होमगार्ड विभाग में रामकिशोर को ड्यूटी करते हो गए आज 1/12/25 को रिटायरमेंट के उपलक्ष में जिला कमांडेंट द्वारा साइकिल देकर रामकिशोर को सम्मान किया इसके पश्चात रेहड़िया पुलिस चौकी इंचार्ज मनोज कुमार ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया होमगार्ड दरोगा महिपाल ने कंबल देकर सम्मानित किया होमगार्ड विभाग में सभी होमगार्ड ने फूलमाला से रामकिशोर का स्वागत बड़े ही धूमधाम

से किया मौके पर उपस्थित रेहड़िया पुलिस चौकी इंचार्ज मनोज कुमार कांस्टेबल विकास कुमार कांस्टेबल संजीव कुमार एवं होमगार्ड विभाग के सभी होमगार्ड मौके पर विदाई समारोह में उपस्थित रहे

बनकोटा पर रोडवेज बस ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर बाइक सवार की मौके पर हुई दर्दनाक मौत बस चालक मौके से हुआ फरार

बदायूं वजीरगंज आज दिनांक 1/12/25 को बबलू यादव सन ऑफ रामगोपाल यादव निवासी ग्राम सिचौली के रहने वाले थे सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि बबलू यादव सन ऑफ रामगोपाल यादव अपनी बहन को बिठाकर घर लौट रहा था तभी तेज रफ्तार रोडवेज बस ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी जिससे बबलू यादव की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई और बस चालक मौके से फरार हो गया सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना वजीरगंज पुलिस ने रोडवेज बस को अपने कब्जे में लिया एवं शव का जांच पड़ताल कर एवं पंचनामा भर के शव को

पोस्टमार्टम के लिए बदायूं भेजा